

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 241/2017

उनवान

समदेव

बनाम

गफूर

अधिवक्ता वादी :- श्री शंकर लाल चौधर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- श्री विवेक चौधरी

निर्णय दिनांक : 7.3.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सी0पी0सी0 व 151 सी0पी0सी0
निर्णय

अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीपीसी व 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि वाद में वादीगण द्वारा इकरारनामों के आधार पर खातेदारी की धोषणा का अनुतोष चाहा है इस कारण प्रस्तुत वाद की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता न्यायालय हाजा को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण वाद वादीगण सी0पी0सी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रारम्भिक स्तर पर क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर ही निरस्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीपीसी व 151 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जावे।


अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि इकरार नामों के आधार पर वाद प्रस्तुत करने के तथ्य वेबूनियादी है। तथा इस बिन्दु के आधार पर निर्णय पूर्व में किया जा चुका है। उक्त वाद का क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दोहराने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी मेन्टेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सी0पी0सी0 व उसके जवाब एवं अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। एवं वाद तथा प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा पेश की गई कानून नजीरे व दस्तावेज के अवलोकन किया वाद में प्रस्तुत अनुतोष एवं संलग्न इकरार नामों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जाना साबित है, जो कि कानूनी नजीरे आर0आर0टी0 2009 (1) पेज न0 643 में भी स्प ट है कि किसी भूमि के बाबत उसे खरिदने के इकरार मात्र से खरीददार भूमि का खातेदार नहीं बन सकता क्योंकि उक्त इकरारनामों के पश्चात् यदि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बयनामा नहीं हुआ तो खरीददार उक्त इकरारनामों के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय में स्पेसीफिक परफार्मेंस का वाद ला सकता है। लेकिन केवल इकरारनामों के आधार पर न तो खरीददार खातेदारी की धोषणा करवा सकता है। और न ही उक्त खरीददार कानाम अन्य प्रकिया द्वारा राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो सकता है और न ही उसे उक्त भूमि को बैचान करने का अधिकार

है। इस लिए इकरारनामों के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद को आरम्भिक स्तर पर क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर निरस्त किये जाने की आवश्यकता है ताकि इकरारनामों के आधार पर भूमि का खरीददार अन्य व्यक्तियों एवं पक्षकारों को भ्रमित न कर सके। आदेश 7 नियम 11 वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि पर खातेदार होने की धोषणा चाही तथा वाद अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट पर आधारित है। एग्रीमेन्ट के आधार पर खातेदारी की धोषणा की क्षेत्राधिकारिता नहीं है प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं चाही लेकिन यह अनुमतिशुद्धा कब्जा है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर खातेदारी का दावा नहीं किया जा सकता है। तथा वाद विधि विरुद्ध पेश करने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी स्वीकार योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले में न्यायालय आज दिनांक 7.3.2018 को सुनाया गया।


(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू